राजनीतिक दलों के लिए विदेशी दान राशियां

2418. **श्री राघवजी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में किन-किन राजनीतिक दलों ने विदेशों से दान राशियां प्राप्त की हैं ;

(ख) यह दान राशियां कब-कब और किन-किन कंपनियों या व्यक्तियों से प्राप्त की गई हैं ; और

(ग) विदेशों से धन पाने वाले उपरोक्त राजनीतिक दलों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993 से 1995 तक की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के बाहर से 3.75 करोड़ रुपये का अभिदाय/दान प्राप्त किया था । यदि अभिदाय/दान देने वाली कंपनियों के नाम :—(i) डेकोर ट्रेडिंग लिमिटेड (ii) डायरा ट्रेडिंग लिमिटेड (iii) डोमिनियन ट्रेडिंग लिमिटेड तथा (iv) बारकेली बिजनेस कारपोरेशन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार, ये सभी भुगतान उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हुए थे।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम , 1976 के प्रावधानों को देखते हुए इस मामले की जांच करने के वास्ते कतिपय ब्यौरे मांगे गए हैं। इस विषय से संबंधित एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित है ।

मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण

2419. **श्री राघव जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होने तथा इसे नक्सलवादियों और डाकुओं से संबंधित पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए सरकार इसे अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) 1996–97 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से 17.98 करोड़ रु. की सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यह सहायता वाहनों के प्रापण, सुरक्षा उपकरण, संचार उपकरण और आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए मांगी गई थी । यद्यपि, आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को आबंटित निधि 1996–97 के दौरान केवल 2.37 करोड़ रु. थी, परन्तु मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना के तहत 4.78 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी । चालू वित्त वर्ष (1997–98) के दौरान 118.910 लाख रु. की सहायता भी उक्त योजना के तहत राज्य सरकार को जारी की गई है ।

Escalation in Cost of Indo-Bangladesh Border Fencing Project

2420. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the tardy implementation of the ambitious multi-crore Indo-Bangladesh Border fencing Project has led too considerable escalation of cost;

(b) if so, the reasons therefor with escalation of cost in terms of money;

(c) whether such fencing project will touch five sensitive States in the North-East Region;